

## वित्त विभाग

## विनियम)

दिनांक 17 अप्रैल, 1984

सं० 3(4)-1234-2-एफ०जी०-II/84—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पंजाब वित्त नियम, जिल्द-I को आग संशोधित करने हेतु हरियाणा राज्यार्थ उन्हें लागू करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब वित्त नियम (हरियाणा चौथा संशोधन) जिल्द-I, नियम 1984 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वित्त नियम, जिल्द-I के नियम 19.9 में क्रमांक 23 और उसके सामने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“23—‘शीर्ष 2.89 प्राकृतिक, अपदाओं (I) ‘उपायुक्त के कारण राहत’ के अर्जीत आवंटन में से खर्च करने के लिए।

किसी भी एक मामले में 3,000 रु० तक किन्तु एक वर्ष में 30,000 रु० (तीस हजार रु०) से अधिक नहीं, परन्तु यदि राशि सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल से उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे, बाढ़ों, आग, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ितों को राहत देने के लिए खर्च की जाती है।

## (II) मण्डल आयुक्त

• किसी भी एक मामले में 5,000 रु० तक किन्तु एक वर्ष में 1,00,000 रु० (एक लाख रुपए) से अधिक नहीं, परन्तु यदि यह राशि सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे बाढ़ों, आग, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ितों को राहत देने के लिए खर्च की जाती है।

## (III) वित्तायुक्त राजस्व

किसी भी एक मामले में 10,000 रु० तक परन्तु यदि यह राशि सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल से उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे, बाढ़ों, आग, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ितों को राहत देने के लिए खर्च की जाती है।”

एल० सी० गुप्ता,

सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

FINANCE DEPARTMENT  
(REGULATIONS)

The 17th April, 1984

No. 3(4)-1234-2FGII-84.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, in their application to the State of Haryana, namely:—

These rules may be called the Punjab Financial Volume I Haryana (fourth Amendment) Rules, 1984.

In the Punjab Financial Rules, Volume I, in rule 19.9, for serial No. 23 and entries there-  
against, the following serial No. and entries shall be substituted, namely:—

“23. To incur expenditure from the allotment under the head “289—Relief on account of Natural Calamities”	(i) Deputy Commissioner	Upto Rs 3,000 in any one case but not exceeding Rs 30,000 in a year; provided the amount is spent to meet the demands arising out of famine in the State and also for the relief of distress caused by serious drought, floods, fire, earthquake or other natural calamities in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.
	(ii) Divisional Commissioners	Upto Rs 5,000 in any one case but not exceeding Rs 1,00,000 in a year; provided the amount is spent to meet the demands arising out of famines in the State and also for the relief of distress caused by serious drought, floods, fire, earthquake or other natural calamities in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.
	(iii) Financial Commissioner, Revenue	Upto limit of Rs 10,000 in any one case: provided the amount is spent to meet the demands arising out of famines in the State and also for the relief of drought, floods, fire, earthquake or other natural calamities in accordance with the instructions issued from time to time.”

M. C. GUPTA,  
Secretary to Government, Haryana,  
Finance Department.

#### FORESTS DEPARTMENT

The 24th/26th April, 1984

No. 1379-Ft-II-84/5173.—The Governor of Haryana is pleased to notify the result of the Departmental Examination of the officers of the Forests Department, Haryana, held in the month of February, 1984 as under :—

Serial No.	Name of officer	Forest Law	Land Revenue	Procedure and Accounts
	<i>S/Shri—</i>			
1	Vinod Kumar Jhahria, HFS.	Pass	Fail	Fail
2	Om Parkash Kaushik, HFS	—	Fail	—
3	Chhotu Ram, IFS	—	Pass	—
4	Ravinder Singh Lamba, HFS	—	—	Fail

G. L. BAILUR,  
Financial Commissioner and  
Secretary to Government, Haryana,  
Forest Department.